(घ) उस विशेष दिन की घटना के संबंध में सरकार द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र की विषय वस्तु और इस समूचे प्रतिवेदन में क्या-क्या अन्तर है ?

गृह मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) से (घ) भारत सरकार को "अयोध्या के बारे में नागरिक अधिकरण" नामक एक प्राइवेट संगठन के अस्तित्व की जानकारी है, जो कि अयोध्या में 6 दिसम्बर, 1992 को घटी घटनाओं से संबंधित मामलों को देख रहा है । 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के लिए जिम्मेदार घटनाक्रम और अन्य संबद्ध घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा, संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गए "अयोध्या पर श्वेत पत्र" में दिया गया है । साथ ही, राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे के विध्वंस से संबंधित मामलों; विभिन्न व्यक्तियों, संबंधित संगठनों और एजेंसियों द्वारा निभाई गई भूमिका; सुरक्षा-उपायों और अन्य प्रबंधों में हुई कमियों तथा किन्हीं अन्य सम्बद्ध मामलों की जांच करना "लिब्रहान अयोध्या जांच आयोग" की जांच की विषय-वस्तु है । 6 दिसम्बर, 1992 की घटनाओं से जुड़े कुछ अपराधों की जांच, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भी है ।

Regrouping by ULFA

2903. SHRI RANJAN PRASAD YADAV: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that ULFA is regrouping in the rural areas of Assam; and

(b) if so, what steps Government propose to take to deal with the situation and what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) There have been some reports about ULFA cadres are trying to re-group in rural areas.

(b) Army operations have been intensified. The Government of Assam have been advised to declare the ULFA hardliners as proclaimed offenders and initiate consequential legal proceedings for attachment, seizure and confiscation of their properties.

कंटीले तारों की बाड़ लगाना

2904. श्री राम जेठमलानी :
डा॰ जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मई, 1993 के दैनिक "ट्रिब्यून" में "बी॰ जी॰ पी॰ सजैस्टस बार्डर फैंसिंग" शिर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने सुझाव दिया है कि आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की गतिविधियों और तस्करी को रोकने के लिए संपूर्ण भारत-पाक सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाई जाए;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझाव के क्रियान्वयन की संभावना पर विचार किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) सरकार ने यह समाचार देखा है किन्तु इस संबंध में पुलिस महानिदेशक, जम्मू एवं कश्मीर से कोई औपचारिक सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । सीमा पर बाड़ लगाना एक सतत प्रक्रिया है और भारत-पाक सीमा के संवेदनशील स्थानों पर बाड़ लगाने का निर्णय लेने से पहले खतरे की आशंका और संसाधनों की उपलब्धता सहित कई घटकों को ध्यान में रखना होगा ।

Dialogue with Terrorist Outfits in Jammu and Kashmir

2905. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to have a dialogue with some terrorist outfits of Kashmir;

(b) if so, the names of such outfits and the details of the dialogue held, if any, so far,

(c) whether it is also a fact that Government propose to have a dialogue with political parties and other relevant organisation in Kashmir, Ladakh and Jammu regions to resume political process in the States;

(d) whether it is also a fact that Government propose to rehabilitate the Kashmir migrants before resuming the political process; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (e) Government is keen to reactivate the political process in Jammu and Kashmir at the earliest Following the dialogue of Union Home Minister with leaders of National Parties, his meeting with former legislators and parliamentarians from the State of Jammu and Kashmir and the visit of a multi-party parliamentary Team to the Kashmir Valley late last year, efforts in this